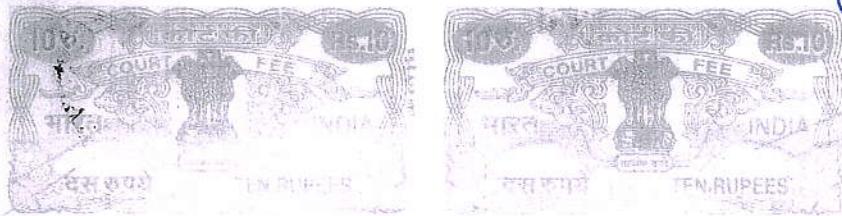


(1)



न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल वालियर केम्प उज्जैन म0 प्र0

१५७८८

नि क. 2014

श्रीमति अमृता बाई पुत्री श्री रामसिंह
पति श्री करण सिंह आयु 45 वर्ष
जाति सेंधव निवासी ग्राम गुराड़िया सुरदास
तहसील टोकखुर्द जिला देवास म0 प्र0

निगरानीकर्ता

— विरुद्ध —

1. जयसिंह आ0 श्री कोक सिंह आयु 36 वर्ष
2. बनेसिंह आ0 श्री कोकसिंह आयु 27 वर्ष
3. अर्केसिंह आ0 श्री कोकसिंह आयु 20 वर्ष
सभी जाति सेंधव निवासी ग्राम ढाबला खालसा
तहसील सोनकच्छ जिला देवास म0 प्र0
4. गीता बाई पुत्री श्री कोक सिंह आयु 40 वर्ष
5. माया बाई पुत्री श्री कोक सिंह आयु 34 वर्ष
6. ममता बाई पुत्री श्री कोक सिंह आयु 30 वर्ष.
सभी जाति सेंधव निवासी ग्राम ढाबला खालसा
तहसील सोनकच्छ जिला देवास म0 प्र0
7. रामकुवर बाई बेवा स्व0 श्री मोतीसिंह आयु 60 वर्ष
8. मांगीलाल आ0 स्व0 श्री मोतीसिंह आयु 40 वर्ष
सभी जाति सेंधव निवासी ग्राम गुराड़िया सुरदास
तहसील टोकखुर्द जिला देवास म0 प्र0

रेस्पोडेंट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भूरा संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.01.
2014 एवं उससे पूर्व अपनाई गई प्रक्रिया प्रकरण क्रमांक 48अ6/2011-12 जयसिंह
आदि विरुद्ध अमृता बाई में पारित द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय टोकखुर्द
तहसील टोकखुर्द जिला देवास

महोदय.

निगरानीकर्ता माननीय जाधारथ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपनाई
प्रक्रिया से असतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नानकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत

प्रकरण क्रमांक – निग. 759-एक / 14

जिला – देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 20-1-14 के विरुद्ध पेश की गई है। तहसीलदार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण लबे समय पूर्ण दायर होना बताया था किंतु समय देने के बाद भी उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण उन्होंने प्रकरण धारा 32 के जबाब हेतु नियत किया है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश में कोई हित किसी तरफ का प्रमाणित नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार पथमदृष्ट्या प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	